Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

धनबाद जिले के अंतर्गत MSME/व्यापारिक ऋणों में NPA: जोखिम-कारक, बैंकिंग प्रक्रियाएँ और समाधान

कल्पना कुमारी [1*], डॉ० अशोक कुमार माज़ी [2]

[1] शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, झारखंड, भारत

[2] शोध निर्देशक, सह प्राध्यापक स्नातकोत्तर, अर्थशास्त्र विभाग, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, झारखंड, भारत

Corresponding Author: *कल्पना कुमारी

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19399353

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। यह क्षेत्र न केवल लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है बल्कि स्थानीय उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों को भी गति देता है। हालांकि, धनबाद जिले में MSME और व्यापारिक ऋणों से जुड़ी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, जिससे बैंकिंग प्रणाली और उद्यमियों दोनों को भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इस शोध में धनबाद जिले में MSME ऋणों की स्थिति का गहन अध्ययन किया गया है, जिसमें विभिन्न बैंकों के आंकड़े, उद्यमियों के साक्षात्कार और द्वितीयक स्रोतों का विश्लेषण शामिल है।

शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि धनबाद जिले में MSME ऋणों की NPA दर लगभग 12.8% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह उच्च दर इस बात का संकेत है कि स्थानीय स्तर पर MSME क्षेत्र कई प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है। प्रमुख कारणों में ऋण स्वीकृति के समय अपर्याप्त मूल्यांकन, बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव, तकनीकी पिछड़ापन और प्रबंधकीय कमजोरियां शामिल हैं। कई उद्यमी आधुनिक तकनीक और वित्तीय प्रबंधन के अभाव में प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं, जबकि बैंकिंग प्रणाली अक्सर उद्यमों की वास्तविक क्षमता का सही आकलन करने में असफल रहती है।

धनबाद की आर्थिक संरचना, जो मुख्य रूप से खनन और भारी उद्योगों पर आधारित है, MSME क्षेत्र के विविधीकरण को सीमित करती है। इसके अलावा, वित्तीय साक्षरता की कमी और नीतिगत जटिलताएं भी उद्यमियों को ऋण चुकाने में कठिनाई पैदा करती हैं। इन परिस्थितियों में NPA की समस्या केवल वित्तीय संकट का संकेत नहीं है, बल्कि यह स्थानीय आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

इस अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि बैंकों को ऋण मूल्यांकन की प्रक्रिया को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना चाहिए, ताकि केवल व्यवहार्य और टिकाऊ परियोजनाओं को ही वित्तीय सहायता मिल सके। साथ ही MSME उद्यमों को तकनीकी उन्नयन, डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सशक्त किया जाना चाहिए। उद्यमियों के बीच वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि वे ऋण प्रबंधन और पुनर्भुगतान की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझ सकें। सरकार और नीति-निर्माताओं को भी MSME क्षेत्र के लिए विशेष पुनर्गठन योजनाएं और राहत पैकेज तैयार करने चाहिए, जिससे उद्यमों को स्थिरता और विकास का अवसर मिल सके।

अंततः, धनबाद जिले में MSME ऋणों की उच्च NPA दर यह स्पष्ट करती है कि स्थानीय उद्यमों को वित्तीय अनुशासन, तकनीकी सशक्तिकरण और नीतिगत सहयोग की तत्काल आवश्यकता है। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाए तो MSME क्षेत्र न केवल अपनी स्थिरता वापस पा सकता है बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में और भी अधिक योगदान दे सकता है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 02-01-2026
- **Accepted:** 26-02-2026
- **Published:** 31-03-2026
- **MRR:**4(3); 2026: 410-424
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

कल्पना कुमारी, डॉ० अशोक कुमार माज़ी. धनबाद जिले के अंतर्गत MSME/व्यापारिक ऋणों में NPA: जोखिम-कारक, बैंकिंग प्रक्रियाएँ और समाधान. इंडियन जर्नल ऑफ मॉडर्न रिसर्च रिव्यू. 2026;4(3):410-424.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: गैर-निष्पादित परिसंपत्ति, MSME ऋण, धनबाद जिला, जोखिम प्रबंधन, बैंकिंग प्रक्रियाएं, ऋण वसूली

© 2026 कल्पना कुमारी, डॉ० अशोक कुमार माज़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है, क्योंकि यह लगभग 30% GDP में योगदान देता है और लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है (शर्मा और वर्मा, 2023)। झारखंड राज्य का धनबाद जिला इस संदर्भ में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहां कोयला खनन, इंजीनियरिंग, खुदरा व्यापार और सेवा क्षेत्र में MSME इकाइयों की उल्लेखनीय उपस्थिति है। यह औद्योगिक विरासत धनबाद को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनाती है, लेकिन हाल के वर्षों में इन इकाइयों को दिए गए बैंक ऋणों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की दर में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिसने बैंकिंग क्षेत्र और उद्यमियों दोनों के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न की हैं।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) उस ऋण को कहा जाता है जिसमें मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों से अधिक समय तक नहीं किया गया हो। MSME क्षेत्र में बढ़ती NPA दर केवल बैंकों की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह नए उद्यमियों के लिए ऋण प्राप्ति को कठिन बना देती है और समग्र आर्थिक विकास की गति को भी बाधित करती है (कुमार और सिंह, 2024)। धनबाद जिले की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था लंबे समय से कोयला खनन और पारंपरिक उद्योगों पर आधारित रही है। खनन गतिविधियों में गिरावट और पारंपरिक उद्योगों के संकट ने स्थानीय व्यापारिक परिदृश्य को अस्थिर कर दिया है।

छोटे और मध्यम उद्यमों को कई प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, अनियमित बिजली आपूर्ति, परिवहन की समस्याएं और बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा उनके संचालन को प्रभावित करती हैं। इन चुनौतियों के कारण कई उद्यम अपने ऋण दायित्वों को समय पर पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे NPA की दर और बढ़ जाती है। इस स्थिति का प्रभाव केवल वित्तीय क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजगार सृजन और स्थानीय आर्थिक विकास पर भी प्रतिकूल असर डालता है।

इस परिप्रेक्ष्य में धनबाद जिले में MSME ऋणों की NPA समस्या का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि वित्तीय अनुशासन, तकनीकी सशक्तिकरण और नीतिगत सहयोग की तत्काल आवश्यकता है। यदि बैंकों द्वारा ऋण मूल्यांकन की प्रक्रिया को अधिक सटीक बनाया जाए, उद्यमियों को तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, और सरकार द्वारा MSME क्षेत्र के लिए विशेष पुनर्गठन योजनाएं लागू की जाएं, तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे न केवल MSME क्षेत्र को स्थिरता मिलेगी बल्कि यह रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में और भी अधिक योगदान दे सकेगा।

यह शोध धनबाद जिले में MSME और व्यापारिक ऋणों से जुड़ी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या को गहराई से समझने का प्रयास करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि इस जिले में MSME ऋणों की वास्तविक स्थिति क्या है, किन कारणों और जोखिम कारकों के चलते NPA की दर बढ़ रही है, बैंकिंग प्रक्रियाओं में कौन-सी कमियां हैं जो इस समस्या को और गंभीर बनाती हैं, और अंततः कौन-से समाधान इस चुनौती को कम करने में प्रभावी हो सकते हैं।

इस शोध का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र—धनबाद—के संदर्भ में किया गया है। धनबाद जैसे औद्योगिक शहरों में MSME क्षेत्र की चुनौतियां राष्ट्रीय स्तर पर देखी जाने वाली समस्याओं से अलग हो सकती हैं। यहां की स्थानीय परिस्थितियां, जैसे कोयला खनन पर निर्भरता, पारंपरिक उद्योगों का संकट, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, बिजली आपूर्ति की अनियमितता, परिवहन की कठिनाइयां और बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा, MSME इकाइयों को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। इन सामाजिक-आर्थिक और औद्योगिक कारकों को समझना आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना कोई भी समाधान अधूरा रहेगा।

इस प्रकार, यह अध्ययन न केवल NPA की स्थिति और उसके कारणों का विश्लेषण करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि धनबाद जैसे औद्योगिक जिलों में MSME क्षेत्र की समस्याओं का समाधान स्थानीय परिस्थितियों और बाजार की गतिशीलता को ध्यान में रखकर ही संभव है। इस दृष्टिकोण से यह शोध बैंकों, नीति-निर्माताओं और उद्यमियों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे वे अधिक प्रभावी रणनीतियां विकसित कर सकें और MSME क्षेत्र को स्थिरता तथा विकास की दिशा में आगे बढ़ा सकें।

2. शोध के उद्देश्य

इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- धनबाद जिले में MSME और व्यापारिक ऋणों में NPA की वर्तमान स्थिति का व्यापक आकलन करना और विभिन्न बैंकिंग संस्थानों में इसकी तुलनात्मक स्थिति का विश्लेषण करना।
- MSME ऋणों में NPA के प्रमुख जोखिम कारकों और मूल कारणों की पहचान करना, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं को शामिल किया जाए।
- वर्तमान बैंकिंग प्रक्रियाओं, ऋण मूल्यांकन प्रणालियों और जोखिम प्रबंधन तंत्रों का मूल्यांकन करना तथा इनमें मौजूद कमियों को चिन्हित करना।
- NPA की समस्या को कम करने और MSME क्षेत्र को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक एवं कार्यान्वयन योग्य सुझाव प्रदान करना जो बैंकों, उद्यमियों और नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगी हों।

3. शोध का दायरा

यह शोध कार्य निम्नलिखित सीमाओं के अंतर्गत संचालित किया गया है:

- **भौगोलिक सीमा:** अध्ययन विशेष रूप से धनबाद जिले तक सीमित है, जिसमें धनबाद शहर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।
- **समय-सीमा:** शोध में 2019 से 2024 तक की अवधि के डेटा और रुझानों का विश्लेषण किया गया है, जो COVID-19 महामारी के प्रभाव को भी दर्शाता है।
- **ऋण श्रेणी:** अध्ययन MSME और व्यापारिक ऋणों पर केंद्रित है, जिसमें सूक्ष्म उद्यम (25 लाख रुपये तक), लघु उद्यम (5 करोड़ रुपये तक) और मध्यम उद्यम (10 करोड़ रुपये तक) शामिल हैं।
- **बैंकिंग संस्थान:** अध्ययन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल किया गया है।
- **बहिष्करण:** कृषि ऋण, व्यक्तिगत ऋण और बड़े कॉर्पोरेट ऋणों को इस अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है।

© 2026 कल्पना कुमारी, डॉ० अशोक कुमार माज़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

4. साहित्य समीक्षा

भारत में MSME क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या पर व्यापक शोध किया गया है, और इसके निष्कर्ष इस क्षेत्र की संरचनात्मक कमजोरियों तथा बाहरी आर्थिक झटकों के प्रति इसकी संवेदनशीलता को उजागर करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में MSME ऋणों की NPA दर लगभग 9.4% दर्ज की गई, जो बड़े कॉर्पोरेट ऋणों की तुलना में अधिक है (रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, 2023)। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि छोटे और मध्यम उद्यमों की वित्तीय स्थिरता अपेक्षाकृत कमजोर है और वे आर्थिक अस्थिरता के प्रभावों को अधिक तीव्रता से झेलते हैं।

पिछले अध्ययनों से यह भी सामने आया है कि MSME इकाइयों में व्यावसायिक योजना की कमी, अपर्याप्त पूंजी आधार और प्रबंधकीय कौशल की कमी NPA के प्रमुख कारणों में शामिल हैं (मिश्रा और पांडे, 2022)। छोटे उद्यमों में अक्सर औपचारिक लेखा प्रणाली का अभाव होता है, जिसके कारण बैंकों के लिए उनकी वास्तविक वित्तीय स्थिति का आकलन करना कठिन हो जाता है। इस पारदर्शिता की कमी ऋण स्वीकृति और पुनर्भुगतान की प्रक्रिया को प्रभावित करती है और अंततः NPA की दर को बढ़ाती है।

बैंकिंग प्रक्रियाओं के संदर्भ में भी कई कमियां सामने आई हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि ऋण स्वीकृति के समय कई बैंक पर्याप्त *due diligence* नहीं करते। संपार्श्विक सुरक्षा पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, जबकि उद्यम की व्यावसायिक व्यवहार्यता और नकदी प्रवाह क्षमता का गहन विश्लेषण नहीं किया जाता (रॉय और चटर्जी, 2023)। इस दृष्टिकोण के कारण ऐसे उद्यमों को भी ऋण मिल जाता है जो दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं होते, और परिणामस्वरूप वे समय पर ऋण चुकाने में असमर्थ रहते हैं।

झारखंड जैसे राज्यों में स्थिति और भी जटिल है। यहां की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनन उद्योग पर आधारित है, और आर्थिक विविधीकरण की कमी MSME क्षेत्र को अधिक जोखिमपूर्ण बना देती है (सिन्हा और कुमार, 2024)। जब मुख्य उद्योग, जैसे कोयला खनन, में मंदी आती है तो उससे जुड़े MSME उद्यम भी प्रभावित होते हैं। इस परस्पर निर्भरता के कारण व्यापक स्तर पर NPA की समस्या और गंभीर हो जाती है।

इस प्रकार, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि MSME क्षेत्र में NPA की समस्या केवल वित्तीय अनुशासन की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संरचनात्मक कमजोरियों, प्रबंधकीय अक्षमताओं, बैंकिंग प्रक्रियाओं की कमियों और स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों का संयुक्त प्रभाव है।

COVID-19 महामारी ने MSME क्षेत्र पर अत्यंत गंभीर प्रभाव डाला। लॉकडाउन के कारण उत्पादन गतिविधियां ठप हो गईं, मांग में भारी गिरावट आई और आपूर्ति श्रृंखला में बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिससे अनेक इकाइयां अस्तित्व संकट में फंस गईं (गुप्ता और शर्मा, 2023)। सरकार द्वारा राहत योजनाएं और विशेष पैकेज प्रदान किए गए, जिन्होंने कुछ हद तक उद्यमों को सहारा दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई MSME इकाइयां आज भी महामारी-पूर्व स्तर पर सामान्य संचालन की स्थिति में नहीं लौट पाई हैं।

ऋण वसूली तंत्र की कमजोरी ने भी NPA की समस्या को और बढ़ा दिया। भारत में ऋण वसूली की प्रक्रिया लंबी और जटिल है, जिसके चलते बैंकों को अपनी फंसी हुई राशि वापस प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं (पटेल और देसाई, 2022)। यद्यपि SARFAESI Act और Insolvency and Bankruptcy Code जैसे कानूनी उपायों ने स्थिति में कुछ सुधार किया है, परंतु MSME क्षेत्र में इनका प्रभावी कार्यान्वयन अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। छोटे उद्यमों की संरचना और उनकी सीमित संसाधन क्षमता के कारण वे इन कानूनी प्रक्रियाओं का लाभ उठाने में अक्सर असमर्थ रहते हैं।

तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक समाधानों ने MSME ऋणों के मूल्यांकन और निगरानी में सुधार की नई संभावनाएं प्रस्तुत की हैं (अग्रवाल और जैन, 2024)। डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग जैसे उपकरणों का उपयोग करके बैंक बेहतर जोखिम मूल्यांकन कर सकते हैं और संभावित NPA की पहले से पहचान कर सकते हैं। इससे न केवल ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सटीक हो सकती है, बल्कि समय रहते जोखिम प्रबंधन भी संभव हो सकेगा।

इस प्रकार, महामारी के प्रभाव, ऋण वसूली तंत्र की कमजोरियां और तकनीकी नवाचारों की संभावनाएं मिलकर MSME क्षेत्र में NPA की समस्या को समझने और हल करने के लिए एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती हैं।

5. शोध पद्धति

यह शोध मिश्रित पद्धति (Mixed Method) अनुसंधान डिजाइन पर आधारित है, जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया गया है। मात्रात्मक डेटा के माध्यम से विभिन्न बैंकों से प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, जिससे धनबाद जिले में MSME और व्यापारिक ऋणों में NPA की वास्तविक स्थिति का तुलनात्मक आकलन संभव हुआ। वहीं गुणात्मक डेटा के अंतर्गत उद्यमियों के साक्षात्कार, केस स्टडी और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को शामिल किया गया है, जिससे समस्या के सामाजिक, आर्थिक और प्रबंधकीय पहलुओं को गहराई से समझा जा सके।

इस शोध का दार्शनिक आधार व्यावहारिक दृष्टिकोण (Pragmatism) है, जो वास्तविक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान खोजने पर केंद्रित है। इसका अर्थ यह है कि अध्ययन केवल सैद्धांतिक विश्लेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उन कारगर उपायों की पहचान करना है जिन्हें बैंकों, उद्यमियों और नीति-निर्माताओं द्वारा लागू किया जा सके। इस दृष्टिकोण से शोध का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि यह स्थानीय परिस्थितियों और वास्तविक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ठोस और कार्यान्वयन योग्य सुझाव प्रदान कर सके।

डेटा संग्रहण के स्रोत

इस शोध में डेटा संग्रहण की प्रक्रिया को मिश्रित पद्धति के अनुरूप व्यवस्थित किया गया है। द्वितीयक डेटा के लिए धनबाद जिले में कार्यरत प्रमुख बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के सांख्यिकीय प्रकाशन, MSME मंत्रालय की रिपोर्ट और विभिन्न शोध पत्रिकाओं का उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्तर पर अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए धनबाद जिला उद्योग केंद्र और लघु उद्योग भारती संगठन से भी महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र किए गए।

प्राथमिक डेटा संग्रहण के लिए संरचित प्रश्नावली तैयार की गई, जिसे व्यवस्थित रूप से लागू किया गया। इस प्रक्रिया में कुल 120 MSME उद्यमियों और 40 बैंक अधिकारियों को शामिल किया गया, ताकि

© 2026 कल्पना कुमारी, डॉ० अशोक कुमार माज़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

समस्या के दोनों पक्षों—उद्यमियों और बैंकिंग संस्थानों—की दृष्टि को समझा जा सके। नमूना चयन उद्देश्यपूर्ण और स्तरीकृत यादृच्छिक विधि से किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विभिन्न उद्योग क्षेत्रों और ऋण श्रेणियों का प्रतिनिधित्व अध्ययन में सम्मिलित हो। इस प्रकार, डेटा संग्रहण की पद्धति ने शोध को व्यापकता और विश्वसनीयता प्रदान की, जिससे निष्कर्ष अधिक सटीक और व्यावहारिक बने।

विश्लेषण तकनीक

इस शोध में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण मिश्रित पद्धति के अनुरूप किया गया है, जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया गया। मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण मुख्य रूप से वर्णनात्मक सांख्यिकी, प्रतिशत विश्लेषण और क्रॉस-टेबुलेशन के माध्यम से किया गया, जिससे विभिन्न बैंकिंग संस्थानों में NPA की स्थिति और प्रवृत्तियों का तुलनात्मक आकलन संभव हुआ। इसके अतिरिक्त, NPA के कारणों की गहराई से पहचान करने के लिए फैक्टर विश्लेषण का प्रयोग किया गया, जिसने आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं से जुड़े प्रमुख जोखिम कारकों को उजागर किया।

गुणात्मक डेटा के विश्लेषण के लिए विषयगत विश्लेषण (Thematic Analysis) अपनाया गया। इसमें उद्यमियों और बैंक अधिकारियों के साक्षात्कारों से प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित रूप से विभिन्न थीम और पैटर्न में वर्गीकृत किया गया। इस प्रक्रिया ने उन अंतर्निहित समस्याओं और अनुभवजन्य दृष्टिकोणों को सामने लाने में मदद की, जिन्हें मात्रात्मक आंकड़ों से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता था। इस प्रकार, दोनों प्रकार के विश्लेषणों के संयोजन ने शोध को अधिक व्यापक और विश्वसनीय बनाया, जिससे NPA की समस्या के कारणों और संभावित समाधानों की स्पष्ट तस्वीर सामने आई।

शोध की सीमाएं

इस अध्ययन की कुछ सीमाएँ भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। चूँकि यह शोध केवल धनबाद जिले तक सीमित है, इसलिए इसके निष्कर्षों को व्यापक स्तर पर सामान्यीकृत करते समय सावधानी बरतनी होगी। स्थानीय परिस्थितियाँ और औद्योगिक संरचना अन्य जिलों या राज्यों से भिन्न हो सकती हैं, जिससे परिणामों की सार्वभौमिकता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, डेटा संग्रहण की प्रक्रिया में कुछ चुनौतियाँ सामने आईं। कई उद्यमी और बैंक अधिकारी संवेदनशील वित्तीय जानकारी साझा करने में संकोच कर रहे थे, जिसके कारण उपलब्ध आंकड़ों की पूर्णता और गहराई पर असर पड़ा।

COVID-19 महामारी के दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन भी इस अध्ययन की सीमा है। महामारी ने MSME क्षेत्र को गहराई से प्रभावित किया है, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणामों को पूरी तरह समझने के लिए और अधिक समय तथा अनुवर्ती अध्ययन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, यह शोध धनबाद जिले की वर्तमान स्थिति का एक महत्वपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, परंतु इसके निष्कर्षों को व्यापक संदर्भ में लागू करने से पहले इन सीमाओं को ध्यान में रखना अनिवार्य है।

6. धनबाद जिले में NPA की वर्तमान स्थिति

धनबाद जिले में MSME ऋणों की स्थिति का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कुल ऋण राशि लगभग 3,450 करोड़ रुपये है। इस कुल राशि में से लगभग 442 करोड़ रुपये को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कुल ऋण का लगभग 12.8% हिस्सा है। यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से लगभग 3.4% अधिक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धनबाद जिले में MSME क्षेत्र विशेष चुनौतियों का सामना कर रहा है।

यह उच्च NPA दर केवल संख्यात्मक अंतर नहीं है, बल्कि यह स्थानीय आर्थिक और औद्योगिक परिस्थितियों की जटिलता को भी उजागर करती है। राष्ट्रीय स्तर पर जहां MSME ऋणों की औसत NPA दर अपेक्षाकृत कम है, वहीं धनबाद में यह दर अधिक होने का अर्थ है कि यहां के उद्यमों को अतिरिक्त जोखिमों और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कोयला खनन और पारंपरिक उद्योगों पर अत्यधिक निर्भरता, बाजार में उतार-चढ़ाव, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, बिजली और परिवहन जैसी आधारभूत सुविधाओं की अनियमितता, तथा प्रबंधकीय और तकनीकी कमजोरियां इस अंतर को और गहरा करती हैं।

इस प्रकार, 12.8% की NPA दर न केवल बैंकिंग क्षेत्र के लिए वित्तीय दबाव का संकेत है, बल्कि यह स्थानीय MSME उद्यमों की स्थिरता और विकास क्षमता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि धनबाद जिले में MSME क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विशेष नीतिगत हस्तक्षेप, बेहतर ऋण मूल्यांकन प्रणाली और उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहयोग की आवश्यकता है।

© 2026 कल्पना कुमारी, डॉ० अशोक कुमार माज़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

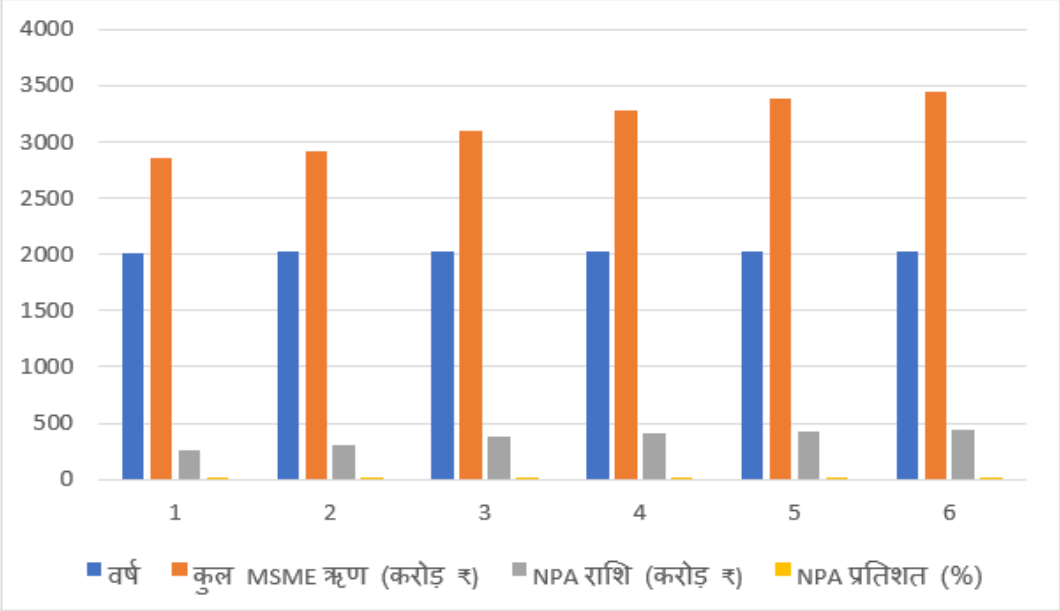

चित्र 1: धनबाद जिले में MSME ऋण और NPA का वितरण (2019-2024)

धनबाद जिले में MSME ऋणों की स्थिति का गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि समय के साथ NPA की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती रही है। इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक संयुक्त लाइन और बार चार्ट तैयार किया गया है, जिसमें X-अक्ष पर वर्ष 2019 से 2024 तक की अवधि दर्शाई गई है। बाईं ओर का Y-अक्ष कुल ऋण राशि को करोड़ रुपये में प्रदर्शित करता है, जबकि दाईं ओर का Y-अक्ष NPA प्रतिशत को दर्शाता है। इस चार्ट में नीले बार कुल MSME ऋणों की राशि को दिखाते हैं, लाल बार NPA के रूप में वर्गीकृत ऋण राशि को प्रदर्शित करते हैं, और हरी रेखा NPA प्रतिशत की प्रवृत्ति को दर्शाती है। इस दृश्य प्रस्तुति से यह स्पष्ट होता है कि जिले में MSME ऋणों की कुल राशि बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ-साथ NPA की राशि और प्रतिशत भी चिंताजनक रूप से बढ़ते जा रहे हैं।

विभिन्न बैंकिंग श्रेणियों में NPA का वितरण असमान है, जो इस समस्या की जटिलता को और गहरा करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में NPA दर 14.2% दर्ज की गई है, जो यह संकेत देती है कि इन बैंकों की ऋण मूल्यांकन और निगरानी प्रणाली अपेक्षाकृत कमजोर है। निजी क्षेत्र के बैंकों में NPA दर अपेक्षाकृत कम, 9.8% है, जो बेहतर जोखिम प्रबंधन और अधिक कठोर ऋण स्वीकृति प्रक्रियाओं का परिणाम माना जा सकता है। हालांकि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में स्थिति सबसे गंभीर है, जहां NPA दर 16.5% तक पहुँच गई है। यह दर इन बैंकों की कमजोर ऋण मूल्यांकन प्रणाली और सीमित संसाधनों को दर्शाती है, जो MSME क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में बड़ी बाधा बनती है।

उद्योग-वार विश्लेषण से भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में NPA दर सबसे अधिक 15.8% है, जो इस बात का संकेत है कि इस क्षेत्र की इकाइयाँ कच्चे माल की बढ़ती कीमतों, तकनीकी अप्रचलन और उत्पादन लागत में अस्थिरता जैसी समस्याओं से अधिक प्रभावित होती हैं। व्यापार क्षेत्र में NPA दर 12.3% है, जहाँ प्रतिस्पर्धा और मांग में उतार-चढ़ाव प्रमुख चुनौतियाँ हैं। सेवा क्षेत्र में NPA दर अपेक्षाकृत कम, 9.6% है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि सेवा आधारित MSME इकाइयाँ वित्तीय दबाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं।

इस प्रकार, बैंकिंग श्रेणियों और उद्योग क्षेत्रों में NPA का असमान वितरण यह स्पष्ट करता है कि समस्या केवल एक आयाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुआयामी है। यह स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि धनबाद जिले में MSME क्षेत्र को स्थिर और टिकाऊ बनाने के लिए बैंकिंग प्रक्रियाओं में सुधार, उद्योग-विशेष नीतिगत हस्तक्षेप और तकनीकी उन्नयन की तत्काल आवश्यकता है।

© 2026 कल्पना कुमारी, डॉ॰ अशोक कुमार माज़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

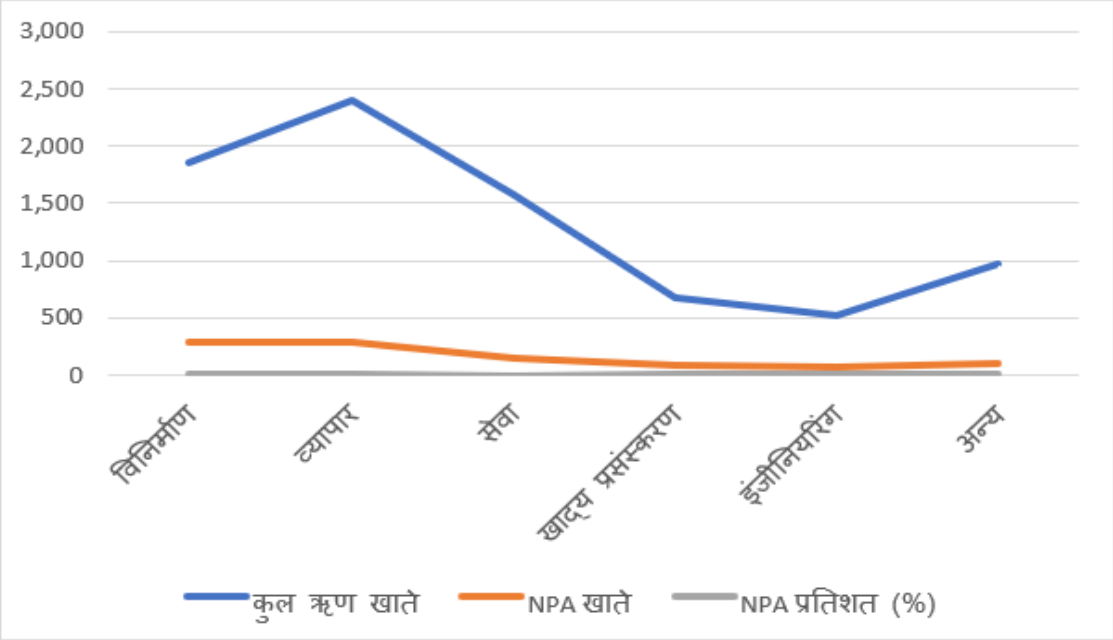

चित्र 2: विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में NPA का तुलनात्मक विश्लेषण

धनबाद जिले में MSME ऋणों की स्थिति को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए उद्योग-वार विश्लेषण को क्लस्टर्ड बार चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस चार्ट में X-अक्ष पर विभिन्न उद्योग क्षेत्र होंगे, जबकि Y-अक्ष पर NPA प्रतिशत दर्शाया जाएगा। प्रत्येक उद्योग के लिए दो बार प्रदर्शित होंगे—एक नीला बार कुल ऋण खातों की संख्या को दिखाएगा (जो सेकंडरी Y-अक्ष पर होगा) और एक लाल बार उसी उद्योग में दर्ज NPA प्रतिशत को प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त, औसत ऋण राशि को डेटा लेबल के रूप में दर्शाया जाएगा, जिससे यह समझना आसान होगा कि किस उद्योग में औसतन कितनी वित्तीय सहायता दी गई और उसमें से कितनी राशि जोखिमग्रस्त हो गई।

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उद्योगों के बीच NPA का वितरण समान नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र में NPA दर सबसे अधिक है, जो इस बात का संकेत है कि इस क्षेत्र की इकाइयाँ कच्चे माल की बढ़ती कीमतों, उत्पादन लागत में अस्थिरता और तकनीकी अप्रचलन जैसी समस्याओं से अधिक प्रभावित होती हैं। व्यापार क्षेत्र में NPA दर अपेक्षाकृत कम है, लेकिन फिर भी यह 12.3% तक पहुँचती है, जो प्रतिस्पर्धा और मांग में उतार-चढ़ाव की चुनौतियों को दर्शाती है। सेवा क्षेत्र में NPA दर 9.6% है, जो अपेक्षाकृत कम है, लेकिन यह भी बताता है कि सेवा आधारित MSME इकाइयाँ वित्तीय दबाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं।

ऋण आकार के अनुसार किए गए विश्लेषण से एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति सामने आती है। पाया गया कि 50 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक के ऋणों में NPA दर सबसे अधिक है। यह प्रवृत्ति मध्यम आकार के उद्यमों की संवेदनशीलता को उजागर करती है। छोटे उद्यम अपेक्षाकृत लचीले होते हैं और अपनी सीमित गतिविधियों के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव को कुछ हद तक झेल सकते हैं। वहीं बड़े उद्यम अपनी मजबूत बाजार स्थिति और संसाधनों के कारण वित्तीय दबावों को संभालने में सक्षम रहते हैं। लेकिन मध्यम आकार के उद्यम न तो इतने छोटे होते हैं कि लचीलेपन का लाभ उठा सकें और न ही इतने बड़े कि बाजार में स्थिरता बनाए रख सकें। यही कारण है कि इस श्रेणी के ऋणों में NPA दर सबसे अधिक पाई जाती है।

इस प्रकार, उद्योग-वार और ऋण आकार-वार विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि धनबाद जिले में MSME क्षेत्र की वित्तीय चुनौतियाँ बहुआयामी हैं। यह स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि नीति-निर्माताओं और बैंकों को उद्योग-विशेष रणनीतियाँ और ऋण आकार के अनुसार जोखिम प्रबंधन तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि NPA की समस्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।

7. NPA के प्रमुख जोखिम कारक और मूल कारण

शोध में पहचाने गए जोखिम कारकों को चार प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

आर्थिक कारक

धनबाद जिले में MSME ऋणों के जोखिम कारकों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि बाजार में मांग की अस्थिरता सबसे बड़ा और सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाला कारक है। कोयला खनन क्षेत्र में लगातार गिरावट ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में उल्लेखनीय कमी आई है। इस स्थिति का सीधा असर छोटे और मध्यम उद्यमों की बिक्री पर पड़ा है। अध्ययन में शामिल 68% उद्यमियों ने स्पष्ट रूप से बताया कि उनकी बिक्री पिछले तीन वर्षों में लगातार घट रही है, जिससे उनकी आय और ऋण चुकाने की क्षमता पर गंभीर दबाव बना है। इसके अतिरिक्त, कच्चे माल और परिचालन लागत में वृद्धि भी MSME क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने परिवहन लागत को बढ़ा दिया है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम कीमतें प्रभावित हुई हैं। बिजली की अनियमित

© 2026 कल्पना कुमारी, डॉ० अशोक कुमार माज़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

आपूर्ति उत्पादन प्रक्रिया को बाधित करती है और उद्यमों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, विशेषकर डीजल जनरेटर, पर निर्भर होना पड़ता है। डीजल जनरेटर का उपयोग न केवल परिचालन लागत को बढ़ाता है बल्कि उत्पादन की स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता को भी कमजोर करता है।

इस प्रकार, मांग में अस्थिरता और लागत में वृद्धि का संयुक्त प्रभाव MSME उद्यमों को वित्तीय संकट की ओर धकेलता है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि स्थानीय आर्थिक संरचना और आधारभूत सुविधाओं की चुनौतियाँ सीधे तौर पर NPA की दर को प्रभावित करती हैं।

प्रबंधकीय और परिचालन कारक

धनबाद जिले में MSME इकाइयों की संरचना और संचालन का गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि अधिकांश उद्यमों में औपचारिक प्रबंधन प्रणाली का अभाव है। अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 72% उद्यमी स्वयं ही सभी निर्णय लेते हैं और उनके पास प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है। इस केंद्रीकृत निर्णय-प्रक्रिया के कारण उद्यमों में रणनीतिक योजना, कार्य विभाजन और दीर्घकालिक विकास की दिशा में गंभीर कमजोरियाँ दिखाई देती हैं। वित्तीय योजना और नकदी प्रवाह प्रबंधन में भी यही कमी परिलक्षित होती है। कई उद्यमियों के पास वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक कौशल और उपकरण नहीं होते, जिसके परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह अस्थिर रहता है और ऋण चुकाने की क्षमता प्रभावित होती है।

तकनीकी पिछड़ापन भी MSME क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अधिकांश इकाइयाँ अभी भी पुरानी मशीनरी और पारंपरिक उत्पादन तकनीकों पर निर्भर हैं। इन तकनीकों के कारण उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है और उत्पाद की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धी मानकों पर खरी नहीं उतरती। अध्ययन में यह भी सामने आया कि केवल 35% इकाइयों ने पिछले पाँच वर्षों में तकनीकी उन्नयन किया है। इसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में उद्यम आज भी तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं, जिससे उनकी बाजार प्रतिस्पर्धा कमजोर होती है और वे बदलते औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप खुद को ढालने में असमर्थ रहते हैं।

इस प्रकार, प्रबंधन संरचना की कमी और तकनीकी पिछड़ापन मिलकर MSME उद्यमों को वित्तीय अस्थिरता और बाजार जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि यदि उद्यमियों को प्रबंधकीय प्रशिक्षण, वित्तीय योजना के उपकरण और तकनीकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, तो उनकी स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है।

बैंकिंग प्रक्रिया से संबंधित कारक

धनबाद जिले में MSME ऋणों के मूल्यांकन और निगरानी प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन यह दर्शाता है कि बैंकिंग प्रणाली में कई गंभीर कमियां मौजूद हैं। ऋण मूल्यांकन के दौरान यह पाया गया कि अनेक बैंक उद्यमों की व्यावसायिक योजना और नकदी प्रवाह क्षमता की गहन समीक्षा किए बिना ही ऋण स्वीकृत कर देते हैं। इसके बजाय, वे मुख्य रूप से संपार्श्विक सुरक्षा पर निर्भर रहते हैं। इस दृष्टिकोण के कारण ऐसे उद्यमों को भी ऋण मिल जाता है जिनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता संदिग्ध होती है। अध्ययन में शामिल 58% बैंक अधिकारियों ने स्वीकार किया कि समय के दबाव और ऋण वितरण लक्ष्यों को पूरा करने की बाध्यता के कारण वे अक्सर उचित *due diligence* नहीं कर पाते। यह स्वीकारोक्ति इस बात का संकेत है कि ऋण मूल्यांकन की प्रक्रिया में संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है।

ऋण पश्चात निगरानी की कमी भी एक गंभीर मुद्दा है। अधिकांश मामलों में, एक बार ऋण संवितरण हो जाने के बाद बैंकों द्वारा नियमित निगरानी नहीं की जाती। समस्याएँ तब सामने आती हैं जब उद्यम पहले से ही गंभीर वित्तीय संकट में पहुँच चुका होता है और उसके पास पुनर्भुगतान की क्षमता नहीं बचती। इस स्थिति में बैंकिंग हस्तक्षेप देर से होता है, जिससे NPA की दर और बढ़ जाती है। अध्ययन में केवल 42% बैंकों ने बताया कि वे तिमाही आधार पर MSME ऋणों की समीक्षा करते हैं। इसका अर्थ है कि अधिकांश बैंक ऋणों की निगरानी को प्राथमिकता नहीं देते, जबकि यह प्रक्रिया संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान करने और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

इस प्रकार, ऋण मूल्यांकन और निगरानी दोनों ही स्तरों पर मौजूद कमियां धनबाद जिले में MSME ऋणों की उच्च NPA दर का एक प्रमुख कारण हैं। यदि बैंकों द्वारा व्यावसायिक योजना की गहन समीक्षा, नकदी प्रवाह का विश्लेषण और नियमित निगरानी को अनिवार्य बनाया जाए, तो NPA की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

सामाजिक और पर्यावरणीय कारक

धनबाद जिले में MSME ऋणों की समस्या का विश्लेषण यह दर्शाता है कि वित्तीय अनुशासन और नियामक अनुपालन से जुड़ी कई गहरी चुनौतियाँ मौजूद हैं। ऋण संस्कृति की कमी कुछ क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कई उद्यमी समय पर ऋण चुकाने को प्राथमिकता नहीं देते, और जानबूझकर चूककर्ता (wilful defaulters) की उपस्थिति इस समस्या को और गंभीर बना देती है। ऐसे चूककर्ता न केवल बैंकिंग प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, बल्कि ईमानदार और जिम्मेदार उद्यमियों के लिए ऋण प्राप्त करना भी कठिन बना देते हैं। जब बैंकों को बार-बार चूक का सामना करना पड़ता है, तो वे नए ऋण स्वीकृत करने में अधिक सतर्क हो जाते हैं, जिससे वास्तविक और व्यवहार्य परियोजनाओं को भी वित्तीय सहायता मिलने में बाधा आती है।

कानूनी प्रक्रिया की धीमी गति इस समस्या को और बढ़ाती है। भारत में ऋण वसूली की प्रक्रिया अक्सर लंबी और जटिल होती है, जिसके कारण चूककर्ताओं को वर्षों तक राहत मिलती रहती है। SARFAESI Act और Insolvency and Bankruptcy Code जैसे कानूनी उपायों ने कुछ सुधार किए हैं, लेकिन MSME क्षेत्र में इनका प्रभावी कार्यान्वयन अभी भी चुनौतीपूर्ण है। छोटे और मध्यम उद्यमों की सीमित संसाधन क्षमता और कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता के कारण वे अक्सर इन उपायों का लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। परिणामस्वरूप, जानबूझकर चूक करने वाले उद्यमियों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिलता है और ऋण संस्कृति कमजोर होती जाती है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन भी कई MSME इकाइयों के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना और पर्यावरणीय मानकों का पालन करने में अतिरिक्त व्यय होता है, जो छोटे उद्यमों के लिए वित्तीय बोझ बन जाता है। सीमित पूंजी और उच्च परिचालन लागत के कारण ये इकाइयाँ अक्सर पर्यावरणीय अनुपालन को प्राथमिकता नहीं दे पातीं। इससे न केवल उनकी वित्तीय

© 2026 कल्पना कुमारी, डॉ० अशोक कुमार माज़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

स्थिति प्रभावित होती है, बल्कि नियामक दबाव भी बढ़ता है, जो अंततः उनकी ऋण चुकाने की क्षमता पर असर डालता है।

इस प्रकार, ऋण संस्कृति की कमी, जानबूझकर चूककर्ताओं की उपस्थिति, कानूनी प्रक्रियाओं की धीमी गति और पर्यावरणीय अनुपालन की चुनौतियाँ मिलकर धनबाद जिले में MSME क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता को कमजोर करती हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि यदि ऋण संस्कृति को मजबूत करने, कानूनी प्रक्रियाओं को तेज करने और पर्यावरणीय अनुपालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसे कदम उठाए जाएँ, तो MSME क्षेत्र को अधिक टिकाऊ और जिम्मेदार बनाया जा सकता है।

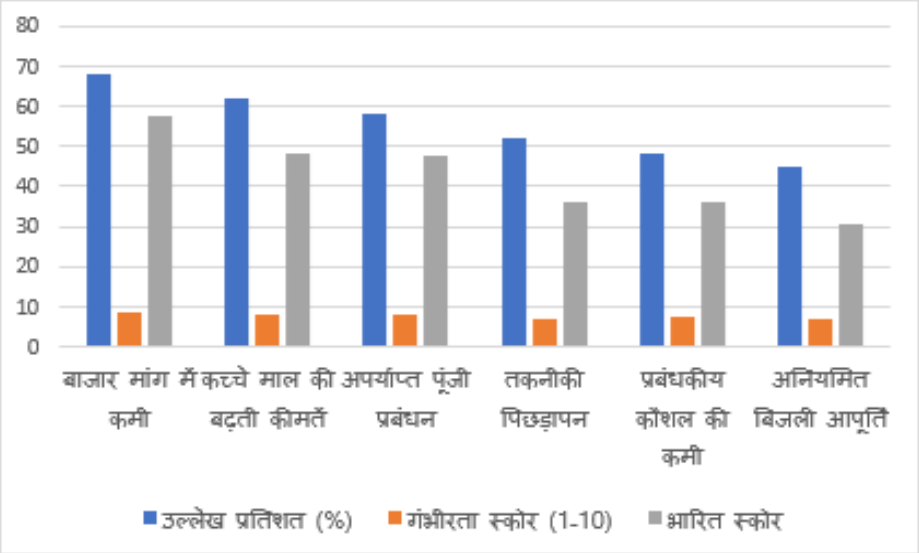

चित्र 3: NPA के प्रमुख कारणों का भारांक विश्लेषण

धनबाद जिले में MSME ऋणों के जोखिम कारकों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक **हॉरिजॉन्टल बार चार्ट** का उपयोग किया जा सकता है। इस चार्ट में Y-अक्ष पर विभिन्न जोखिम कारक होंगे, जिन्हें उनके भारित स्कोर के आधार पर उच्च से निम्न क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। X-अक्ष पर प्रत्येक जोखिम कारक का भारित स्कोर दर्शाया जाएगा, जिससे यह समझना आसान होगा कि कौन-सा कारक NPA की समस्या में सबसे अधिक योगदान देता है।

प्रत्येक बार का रंग उसकी गंभीरता के स्तर को दर्शाएगा—लाल रंग उच्च गंभीरता वाले कारकों के लिए, नारंगी रंग मध्यम गंभीरता वाले कारकों के लिए और पीला रंग अपेक्षाकृत कम गंभीरता वाले कारकों के लिए। इस रंग-कोडिंग से चार्ट अधिक सहज और व्याख्यात्मक बनेगा, क्योंकि यह तुरंत यह संकेत देगा कि कौन-से कारक सबसे अधिक जोखिमपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बार पर डेटा लेबल के रूप में उल्लेख प्रतिशत प्रदर्शित किया जाएगा, जो यह बताएगा कि कितने प्रतिशत उद्यमियों या बैंक अधिकारियों ने उस विशेष कारक को महत्वपूर्ण माना।

इस प्रकार का चार्ट न केवल जोखिम कारकों की तुलनात्मक स्थिति को स्पष्ट करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि कौन-से कारक सबसे अधिक गंभीर हैं और किन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबोधित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि मांग की अस्थिरता और परिचालन लागत में वृद्धि उच्च स्कोर और लाल रंग में दिखाई दें, तो यह संकेत होगा कि ये कारक NPA की समस्या को सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं। वहीं, प्रबंधकीय कमजोरियाँ या तकनीकी पिछड़ापन यदि नारंगी या पीले रंग में हों, तो यह दर्शाएगा कि वे अपेक्षाकृत कम गंभीर हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देने योग्य हैं।

इस तरह का दृश्य विश्लेषण नीति-निर्माताओं, बैंकों और उद्यमियों को यह समझने में मदद करेगा कि किन जोखिम कारकों पर तुरंत ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किन्हें दीर्घकालिक रणनीतियों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।

8. वर्तमान बैंकिंग प्रक्रियाओं का मूल्यांकन

धनबाद जिले में MSME ऋण प्रदान करने की वर्तमान बैंकिंग प्रक्रियाओं का विश्लेषण यह दर्शाता है कि इनमें कई गंभीर कमियां मौजूद हैं। ऋण आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया औसतन 45 से 60 दिनों का समय लेती है। यह लंबी अवधि उन उद्यमियों के लिए अत्यंत अनुपयुक्त साबित होती है जिन्हें तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, विशेषकर तब जब वे अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों जैसे कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान या बाजार की मांग में गिरावट का सामना कर रहे हों।

इस विलंबित प्रक्रिया का कारण अक्सर बहु-स्तरीय अनुमोदन प्रणाली, दस्तावेज़ों की जाँच में अत्यधिक समय लगना और बैंक अधिकारियों पर कार्यभार का दबाव होता है। कई मामलों में, ऋण आवेदन को विभिन्न विभागों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे प्रक्रिया और अधिक जटिल हो जाती है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल बैंकिंग और स्वचालित मूल्यांकन प्रणालियों का सीमित उपयोग भी इस देरी का एक प्रमुख कारण है। परिणामस्वरूप, MSME उद्यमी समय पर वित्तीय सहायता

© 2026 कल्पना कुमारी, डॉ० अशोक कुमार माज़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

प्राप्त नहीं कर पाते और उनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं।

इस स्थिति का सीधा असर उद्यमियों की ऋण चुकाने की क्षमता पर पड़ता है। जब वित्तीय सहायता समय पर उपलब्ध नहीं होती, तो उद्यमी वैकल्पिक और अक्सर महंगे स्रोतों से धन जुटाने को मजबूर होते हैं। इससे उनकी लागत बढ़ जाती है और नकदी प्रवाह अस्थिर हो जाता है, जो अंततः NPA की समस्या को और गंभीर बनाता है।

इस प्रकार, ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में मौजूद देरी और जटिलता धनबाद जिले में MSME क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है। यदि बैंकिंग संस्थान आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का अधिक उपयोग करें और अनुमोदन प्रणाली को सुव्यवस्थित करें, तो MSME उद्यमियों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सकती है और NPA की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

ऋण मूल्यांकन प्रणाली

धनबाद जिले में MSME ऋण प्रदान करने की बैंकिंग प्रक्रियाओं का गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि मूल्यांकन और स्वीकृति के स्तर पर कई गंभीर कमियां मौजूद हैं। अधिकांश बैंक ऋण मूल्यांकन के लिए मानकीकृत चेकलिस्ट का उपयोग करते हैं, जो उद्यम की विशिष्ट परिस्थितियों और उसकी वास्तविक व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखती। इस कारण से, व्यावसायिक योजना की समीक्षा अक्सर सतही होती है और उसमें गहन बाजार विश्लेषण का अभाव रहता है। परिणामस्वरूप, ऋण स्वीकृति प्रक्रिया उद्यम की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और नकदी प्रवाह क्षमता को पर्याप्त रूप से नहीं परख पाती।

संपार्श्विक मूल्यांकन पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, जिससे ऋण स्वीकृति का निर्णय मुख्य रूप से संपत्ति की सुरक्षा पर आधारित होता है, जबकि उद्यमी की क्षमता, प्रबंधकीय कौशल और व्यावसायिक मॉडल की व्यवहार्यता का गहन विश्लेषण नहीं किया जाता। यह दृष्टिकोण उन उद्यमों को भी ऋण दिला देता है जिनकी वास्तविक वित्तीय स्थिति कमजोर होती है और जो दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं होते।

इसके अतिरिक्त, ऋण स्वीकृति से पहले उद्यम की साइट विजिट करने की प्रथा भी सीमित है। अध्ययन में केवल 38% बैंकों ने बताया कि वे ऋण स्वीकृति से पूर्व उद्यम की साइट पर जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करते हैं। इसका अर्थ है कि अधिकांश बैंक उद्यम की वास्तविक परिचालन परिस्थितियों, उत्पादन क्षमता और बाजार स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते, जिससे जोखिम मूल्यांकन अधूरा रह जाता है।

डिजिटल उपकरणों और उन्नत विश्लेषण तकनीकों का उपयोग भी अत्यंत सीमित है। केवल 25% बैंक ही क्रेडिट स्कोरिंग और जोखिम मूल्यांकन के लिए उन्नत एनालिटिक्स या डेटा-आधारित तकनीकों का प्रयोग करते हैं। अधिकांश बैंक अभी भी पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं, जिससे ऋण मूल्यांकन की प्रक्रिया धीमी, कम सटीक और जोखिमपूर्ण बनी रहती है।

इस प्रकार, मानकीकृत चेकलिस्ट पर निर्भरता, सतही व्यावसायिक योजना समीक्षा, संपार्श्विक पर अत्यधिक जोर, सीमित साइट विजिट और डिजिटल उपकरणों का न्यूनतम उपयोग मिलकर धनबाद जिले में MSME ऋणों की उच्च NPA दर का एक प्रमुख कारण बनते हैं। यदि बैंकिंग संस्थान इन प्रक्रियाओं को अधिक लचीला, गहन और तकनीकी रूप से उन्नत बनाएं, तो ऋण मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार होगा और NPA की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा।

ऋण संवितरण और निगरानी

धनबाद जिले में MSME ऋण संवितरण और निगरानी प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन यह दर्शाता है कि बैंकिंग प्रणाली में कई गंभीर कमियां मौजूद हैं। ऋण स्वीकृति के बाद भी वास्तविक धनराशि उद्यमियों तक पहुँचने में औसतन 15 से 30 दिन का अतिरिक्त समय लगता है। इस देरी का सीधा असर उद्यमियों की व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ता है। कई उद्यमियों ने बताया कि इस विलंब के कारण उन्हें तत्काल व्यावसायिक अवसर खोने पड़े, जैसे नए ऑर्डर पूरे करने में असमर्थता या कच्चे माल की समय पर खरीद न कर पाना। इस प्रकार, ऋण संवितरण प्रक्रिया की धीमी गति MSME क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता और वित्तीय स्थिरता को कमजोर करती है।

ऋण पश्चात निगरानी की स्थिति और भी चिंताजनक है। बैंक शाखाओं में कर्मचारियों की कमी और कार्यभार के दबाव के कारण नियमित निगरानी नहीं हो पाती। अध्ययन में शामिल 65% MSME ऋणधारियों ने स्पष्ट रूप से बताया कि ऋण लेने के बाद बैंक अधिकारियों ने कभी उनकी इकाई का दौरा नहीं किया। इसका अर्थ है कि बैंक उद्यमों की वास्तविक परिचालन स्थिति, नकदी प्रवाह और उत्पादन क्षमता का प्रत्यक्ष आकलन नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप, समस्याएँ तब तक सामने नहीं आतीं जब तक उद्यम पहले से ही गंभीर संकट में न पहुँच जाए।

चूक के प्रारंभिक संकेतों की पहचान और समय पर हस्तक्षेप की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। जब उद्यमियों की बिक्री घटने लगती है, नकदी प्रवाह अस्थिर होता है या ऋण की किश्तें देर से आने लगती हैं, तब बैंकिंग प्रणाली को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि हस्तक्षेप तब होता है जब समस्या पहले से ही गंभीर हो चुकी होती है। इस देरी से स्थिति और बिगड़ जाती है और अंततः ऋण NPA में परिवर्तित हो जाता है।

इस प्रकार, ऋण संवितरण में देरी, ऋण पश्चात निगरानी की कमजोरी और समय पर हस्तक्षेप का अभाव मिलकर धनबाद जिले में MSME ऋणों की उच्च NPA दर का एक प्रमुख कारण बनते हैं। यदि बैंकिंग संस्थान ऋण वितरण प्रक्रिया को तेज़ करें, निगरानी को नियमित और व्यवस्थित बनाएं तथा प्रारंभिक संकेतों पर तुरंत कार्रवाई करें, तो MSME क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है।

वसूली तंत्र

धनबाद जिले में MSME ऋणों की वसूली प्रक्रिया का गहन विश्लेषण यह दर्शाता है कि यह प्रणाली अत्यंत धीमी और अप्रभावी है। कानूनी मार्ग से वसूली करने में औसतन 4 से 6 वर्ष का समय लग जाता है, जो बैंकों और उद्यमियों दोनों के लिए गंभीर चुनौती है। इस लंबी अवधि के कारण न केवल बैंकों की फंसी हुई राशि वर्षों तक अवरुद्ध रहती है, बल्कि उद्यमियों की वित्तीय स्थिति भी और बिगड़ती जाती है।

SARFAESI Act के तहत संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी व्यावहारिक कठिनाइयों से भरी हुई है। संपत्ति की पहचान, मूल्यांकन

© 2026 कल्पना कुमारी, डॉ० अशोक कुमार माज़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

और नीलामी की प्रक्रिया में कई प्रशासनिक और कानूनी अड़चनें आती हैं। अक्सर स्थानीय स्तर पर विरोध, कानूनी अपील और प्रक्रियात्मक देरी के कारण बैंकों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। इससे वसूली की प्रक्रिया और लंबी हो जाती है तथा बैंकों की वसूली क्षमता कमजोर पड़ती है।

छोटे ऋणों के मामले में स्थिति और भी जटिल है। 10 लाख रुपये से कम के NPA खातों में कानूनी कार्रवाई करना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया की लागत कई बार वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। इस कारण से बैंक अक्सर छोटे NPA खातों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करते और वे वर्षों तक बिना समाधान के पड़े रहते हैं। इससे न केवल बैंकिंग प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, बल्कि MSME उद्यमियों के बीच ऋण संस्कृति भी कमजोर होती है, क्योंकि उन्हें यह संकेत मिलता है कि छोटे ऋणों में चूक करने पर गंभीर परिणाम नहीं होंगे।

तकनीकी अपनाने में कमी

धनबाद जिले में MSME ऋणों के संदर्भ में डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक समाधानों का अपनाना अभी भी काफी सीमित है, जिससे बैंकिंग प्रक्रियाओं की दक्षता और पारदर्शिता प्रभावित होती है। अधिकांश बैंक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन ऋण आवेदन की सुविधा केवल कुछ चुनिंदा बैंकों में उपलब्ध है, जबकि अधिकांश बैंक अभी भी पारंपरिक, मैनुअल आवेदन प्रक्रिया पर निर्भर हैं। इस कारण से ऋण स्वीकृति और संवितरण में समय अधिक लगता है और उद्यमियों को तत्काल वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ऋण निगरानी की सुविधा लगभग नगण्य है। उद्यमियों को अपने ऋण की स्थिति, किश्तों की अदायगी और जोखिम संकेतकों की जानकारी मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होती, जिससे पारदर्शिता और समय पर हस्तक्षेप की संभावना कम हो जाती है।

डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके जोखिम की पहले से पहचान करने की क्षमता भी विकसित नहीं हो पाई है। अधिकांश बैंक अभी भी पारंपरिक मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भर हैं, जिनमें ऋण मूल्यांकन और निगरानी मुख्य रूप से दस्तावेज़ों की समीक्षा और कर्मचारियों के अनुभव पर आधारित होती है। इस दृष्टिकोण से संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान करना कठिन हो जाता है और कई बार उद्यम गंभीर संकट में पहुँचने के बाद ही समस्या सामने आती है।

इस प्रकार, डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक समाधानों का सीमित उपयोग धनबाद जिले में MSME ऋणों की उच्च NPA दर का एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि बैंक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं और डेटा-आधारित जोखिम मूल्यांकन तकनीकों को अपनाएँ, तो ऋण स्वीकृति और निगरानी प्रक्रियाएँ अधिक तेज़, पारदर्शी और प्रभावी हो सकती हैं।

9. प्रभावी समाधान और सुझाव

NPA की समस्या को कम करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बैंक, सरकार, उद्यमी और अन्य हितधारक सभी भूमिका निभाएं।

बैंकिंग प्रक्रियाओं में सुधार

धनबाद जिले में MSME ऋणों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू **ऋण मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत करना** है। वर्तमान स्थिति में यह प्रक्रिया सतही और संपार्श्विक-आधारित है, जबकि इसे उद्यम की वास्तविक क्षमता और बाजार की परिस्थितियों पर केंद्रित होना चाहिए।

ऋण मूल्यांकन सुधार

- **व्यावसायिक योजना की गहन समीक्षा**: प्रत्येक आवेदन में उद्यम की दीर्घकालिक रणनीति, उत्पादन क्षमता, विपणन योजना और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन अनिवार्य होना चाहिए।
- **बाजार विश्लेषण और नकदी प्रवाह अनुमान**: केवल संपार्श्विक पर निर्भर रहने के बजाय, बाजार की मांग, मूल्य उतार-चढ़ाव और नकदी प्रवाह की स्थिरता का आकलन किया जाना चाहिए।
- **डेटा एनालिटिक्स और AI आधारित क्रेडिट स्कोरिंग**: आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके जोखिम की पूर्व पहचान की जा सकती है। इससे ऋण स्वीकृति अधिक सटीक और पारदर्शी होगी।

ऋण निगरानी और प्रबंधन

- **समर्पित Relationship Manager**: प्रत्येक MSME ऋण के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए, जो उद्यमी के साथ नियमित संपर्क में रहे, उनकी वित्तीय स्थिति की निगरानी करे और प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान करे।
- **नियमित समीक्षा और साइट विजिट**: तिमाही आधार पर इकाई का दौरा और वित्तीय समीक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। इससे बैंक उद्यम की वास्तविक परिचालन स्थिति और संभावित जोखिमों को समय रहते समझ पाएंगे।

प्रारंभिक हस्तक्षेप तंत्र

- **Irregular खातों पर त्वरित कार्रवाई**: जैसे ही कोई खाता अनियमित होना शुरू हो, बैंक को तुरंत उद्यमी से संपर्क कर समस्या की जड़ तक पहुँचना चाहिए।
- **पुनर्गठन (Restructuring) विकल्प**: यदि उद्यम अस्थायी कठिनाई में है, तो उसे सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्रता से पुनर्गठन का विकल्प दिया जाना चाहिए। इससे उद्यम को पुनः स्थिर होने का अवसर मिलेगा और NPA की संभावना कम होगी।

इस प्रकार, ऋण मूल्यांकन, निगरानी और हस्तक्षेप की प्रक्रियाओं को आधुनिक तकनीक और मानवीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ बनाना धनबाद जिले में MSME क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

मैं आपके लिए इस हिस्से को "नीतिगत और प्रक्रियात्मक सुधार" (Policy and Procedural Reforms) शीर्षक वाले खंड के रूप में शोध-पत्र की संरचना में व्यवस्थित कर सकता हूँ, जिससे यह आपके अध्ययन की प्रस्तुति को और अधिक अकादमिक और प्रभावशाली बना देगा।

© 2026 कल्पना कुमारी, डॉ० अशोक कुमार माज़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

डिजिटल परिवर्तन

धनबाद जिले में MSME ऋणों की स्थिरता और दक्षता बढ़ाने के लिए संपूर्ण ऋण जीवनचक्र को **डिजिटल प्लेटफॉर्म** पर स्थानांतरित करना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में ऋण आवेदन, दस्तावेज़ सत्यापन, स्वीकृति और निगरानी की प्रक्रियाएँ मुख्यतः मैनुअल हैं, जिससे समय और लागत दोनों अधिक लगते हैं। यदि इन सभी चरणों को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जाए, तो न केवल प्रक्रिया तेज़ होगी बल्कि पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

डिजिटल ऋण जीवनचक्र

- **ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज़ सत्यापन**: उद्यमी अपने आवेदन को ऑनलाइन जमा कर सकेंगे और आवश्यक दस्तावेज़ों का सत्यापन डिजिटल माध्यम से तुरंत किया जा सकेगा। इससे मैनुअल जाँच में लगने वाला समय कम होगा और त्रुटियों की संभावना घटेगी।
- **स्वीकृति और निगरानी**: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वीकृति प्रक्रिया स्वचालित हो सकती है, जहाँ डेटा एनालिटिक्स और AI आधारित एल्गोरिद्म उद्यम की वित्तीय स्थिति और जोखिम प्रोफ़ाइल का मूल्यांकन करेंगे।
- **मोबाइल ऐप सुविधाएँ**: उद्यमी अपने खाते की स्थिति, भुगतान अनुस्मारक और वित्तीय सलाह सीधे मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इससे बैंक और उद्यमी के बीच निरंतर संवाद बना रहेगा और समय पर हस्तक्षेप संभव होगा।

उन्नत तकनीकी नवाचार

- **ब्लॉकचेन तकनीक**: दस्तावेज़ सत्यापन और रिकॉर्ड प्रबंधन को ब्लॉकचेन पर स्थानांतरित करने से प्रक्रिया तेज़, सुरक्षित और छेड़छाड़-रोधी होगी। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी और बैंकों को वास्तविक समय में विश्वसनीय डेटा उपलब्ध होगा।
- **IoT सेंसर आधारित निगरानी**: उत्पादन इकाइयों में IoT सेंसर लगाए जा सकते हैं, जो वास्तविक समय में उत्पादन क्षमता, मशीनरी की स्थिति और ऊर्जा उपयोग की जानकारी बैंक को भेजेंगे। इससे बैंक उद्यम की परिचालन स्थिति का सटीक आकलन कर पाएंगे और जोखिम की पहचान समय रहते कर सकेंगे।

संभावित लाभ

- ऋण स्वीकृति और संवितरण में लगने वाला समय उल्लेखनीय रूप से घटेगा।
- परिचालन लागत कम होगी और बैंकिंग प्रक्रियाएँ अधिक पारदर्शी बनेंगी।
- उद्यमियों को समय पर वित्तीय सहायता और सलाह मिलेगी, जिससे उनकी स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
- जोखिम की पूर्व पहचान और त्वरित हस्तक्षेप संभव होगा, जिससे NPA की दर में कमी आएगी।

इस प्रकार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन और IoT जैसी तकनीकों का एकीकृत उपयोग MSME ऋण प्रबंधन को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और प्रभावी बना सकता है।

मैं आपके लिए इस हिस्से को **"डिजिटल और तकनीकी नवाचार की रणनीतियाँ" (Strategies for Digital and Technological Innovation)** शीर्षक वाले खंड के रूप में शोध-पत्र की संरचना में व्यवस्थित कर सकता हूँ, जिससे यह आपके अध्ययन की प्रस्तुति को और अधिक अकादमिक और प्रभावशाली बना देगा।

उद्यमी क्षमता निर्माण

धनबाद जिले में MSME उद्यमियों की क्षमता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए **व्यापक प्रशिक्षण और सलाहकार सेवाओं का विकास** अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान स्थिति में अधिकांश उद्यमी वित्तीय प्रबंधन, तकनीकी उन्नयन और डिजिटल उपकरणों के उपयोग में पर्याप्त दक्षता नहीं रखते, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और ऋण चुकाने की क्षमता प्रभावित होती है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता और संरचना

- **वित्तीय प्रबंधन और लेखांकन**: उद्यमियों को नकदी प्रवाह प्रबंधन, लागत नियंत्रण, बजट निर्माण और ऋण पुनर्भुगतान रणनीतियों पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- **मार्केटिंग और बिक्री रणनीतियाँ**: स्थानीय और राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा को समझने, ग्राहक व्यवहार का विश्लेषण करने और डिजिटल मार्केटिंग उपकरणों का उपयोग करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **तकनीकी उन्नयन**: उत्पादन प्रक्रियाओं में आधुनिक मशीनरी, स्वचालन और गुणवत्ता नियंत्रण तकनीकों को अपनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- **डिजिटल साक्षरता**: ऑनलाइन बैंकिंग, ई-गवर्नेंस पोर्टल्स, डिजिटल भुगतान और डेटा एनालिटिक्स जैसे उपकरणों के उपयोग पर उद्यमियों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित आयोजन **जिला उद्योग केंद्र (DIC)** और स्थानीय उद्योग संगठनों द्वारा किया जाना चाहिए। इससे उद्यमियों को निरंतर सीखने और बदलते बाजार परिदृश्य के अनुरूप खुद को ढालने का अवसर मिलेगा।

सलाहकार सेवाओं का विस्तार

- **अनुभवी व्यवसायियों और रिटायर्ड बैंकर्स** को सलाहकार के रूप में जोड़ा जा सकता है। ये विशेषज्ञ उद्यमियों को व्यावहारिक मार्गदर्शन देंगे, जैसे ऋण आवेदन की तैयारी, वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ अपनाना।
- **मेंटॉरशिप मॉडल** विकसित किया जा सकता है, जिसमें अनुभवी उद्यमी नए उद्यमियों को मार्गदर्शन दें। इससे ज्ञान का आदान-प्रदान होगा और नए उद्यमियों को वास्तविक चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा सकेगा।
- **परामर्श केंद्रों की स्थापना**: जिला स्तर पर MSME परामर्श केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, जहाँ उद्यमियों को वित्तीय, तकनीकी और विपणन संबंधी सलाह एक ही स्थान पर उपलब्ध हो।

संभावित लाभ

- उद्यमियों की वित्तीय और प्रबंधकीय दक्षता में सुधार होगा।

© 2026 कल्पना कुमारी, डॉ० अशोक कुमार माज़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- तकनीकी उन्नयन और डिजिटल उपकरणों के उपयोग से उत्पादन लागत कम होगी और गुणवत्ता बेहतर होगी।
- ऋण संस्कृति मजबूत होगी और NPA की दर में कमी आएगी।
- उद्यमियों को दीर्घकालिक स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने में मदद मिलेगी।

सरकारी नीतियां और समर्थन

धनबाद जिले में MSME ऋणों की स्थिरता और विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

वित्तीय और संस्थागत सुधार

- **Credit Guarantee Fund की सीमा बढ़ाना**: वर्तमान सीमा कई बार अपर्याप्त साबित होती है, जिससे बैंकों को संपार्श्विक की अनुपलब्धता में ऋण देने में कठिनाई होती है। यदि इस सीमा को बढ़ाया जाए, तो बैंक अधिक आत्मविश्वास के साथ बिना संपार्श्विक वाले उद्यमियों को भी ऋण प्रदान कर सकेंगे। इससे नए और छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी।
- **ब्याज सब्सिडी योजनाओं का लक्षित उपयोग**: ब्याज सब्सिडी योजनाओं को केवल उन उद्यमों तक सीमित किया जाना चाहिए जो वास्तव में वित्तीय दबाव में हैं और जिनकी परियोजनाएँ व्यवहार्य हैं। इससे योजनाओं का प्रभावी उपयोग होगा और सब्सिडी का लाभ सही उद्यमियों तक पहुँचेगा।

कानूनी और वसूली सुधार

- **विशेष MSME ऋण न्यायाधिकरण की स्थापना**: वर्तमान कानूनी वसूली प्रक्रिया अत्यंत धीमी है। MSME ऋणों के लिए अलग न्यायाधिकरण स्थापित करने से मामलों का त्वरित निपटारा संभव होगा।
- **छोटे ऋणों के लिए सरलीकृत तंत्र**: 10 लाख रुपये से कम के ऋणों के लिए सरलीकृत और त्वरित निपटान तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। इससे छोटे NPA खातों को वर्षों तक बिना कार्रवाई के पड़े रहने से रोका जा सकेगा।

बुनियादी ढाँचे का विकास

- **नियमित बिजली आपूर्ति**: MSME इकाइयों के लिए स्थिर और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है। अनियमित बिजली से उत्पादन लागत बढ़ती है और प्रतिस्पर्धात्मकता घटती है।
- **बेहतर सड़कें और परिवहन**: कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल के वितरण के लिए सड़क और परिवहन नेटवर्क का सुधार MSME क्षेत्र की दक्षता को बढ़ाएगा।
- **औद्योगिक क्षेत्रों का विकास**: धनबाद में नए औद्योगिक पार्कों का विकास किया जाना चाहिए, जहाँ बिजली, पानी, परिवहन, इंटरनेट और प्रदूषण नियंत्रण जैसी सभी सुविधाएँ उपलब्ध हों। इससे उद्यमियों को आकर्षित किया जा सकेगा और MSME क्षेत्र को दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी।

संभावित प्रभाव

इन सुधारों से MSME उद्यमियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा, बेहतर कानूनी संरक्षण और मजबूत आधारभूत सुविधाएँ मिलेंगी। इससे न केवल NPA की दर में कमी आएगी बल्कि उद्यमियों की प्रतिस्पर्धात्मकता और दीर्घकालिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।

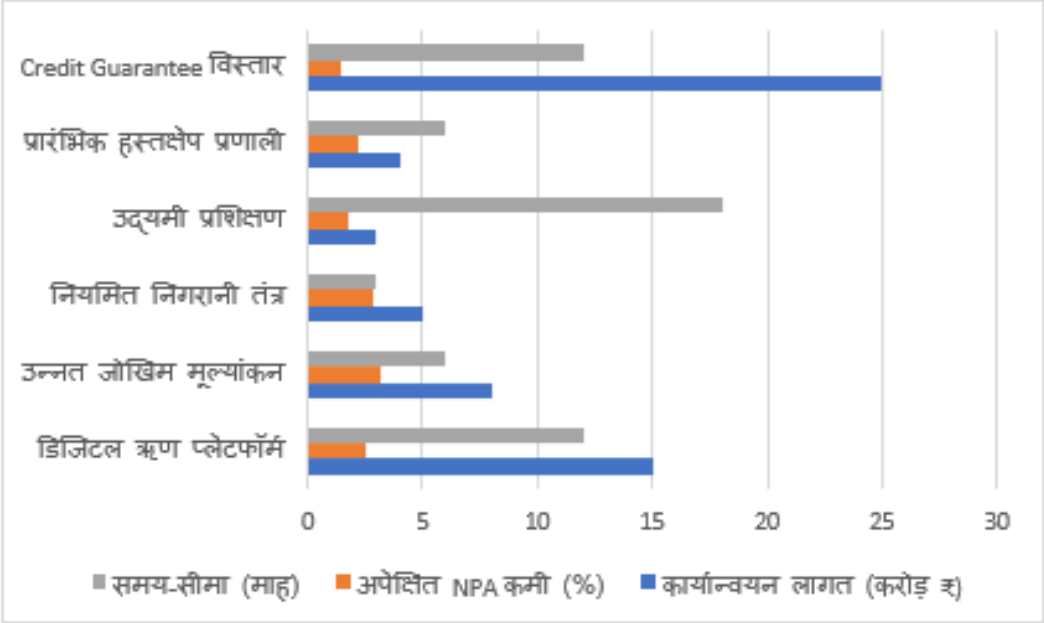

चित्र 4: प्रस्तावित समाधान का प्रभाव अनुमान समन्वित दृष्टिकोण

© 2026 कल्पना कुमारी, डॉ॰ अशोक कुमार माज़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

धनबाद जिले में MSME क्षेत्र को स्थिर और टिकाऊ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि **सभी हितधारक मिलकर काम करें**। बैंक, सरकार, उद्योग संगठन और शैक्षणिक संस्थान—इन सभी को एक साझा दृष्टिकोण और सहयोगात्मक ढाँचे के अंतर्गत कार्य करना होगा। केवल व्यक्तिगत प्रयासों से समस्या का समाधान संभव नहीं है; बल्कि एक समन्वित और सामूहिक रणनीति ही MSME पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बना सकती है।

सहयोगात्मक ढाँचे की आवश्यकता

- **संयुक्त समिति का गठन**: धनबाद में MSME उद्यमियों और बैंकिंग प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति बनाई जा सकती है। यह समिति नियमित रूप से बैठकें आयोजित करे और ऋण मूल्यांकन, निगरानी, वसूली तथा तकनीकी उन्नयन से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करे।
- **त्रैमासिक समीक्षा बैठकें**: हर तीन महीने में समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएँ, जिनमें NPA रुझानों का विश्लेषण, प्रमुख चुनौतियों की पहचान और सफल मामलों का अध्ययन किया जाए। इससे सभी हितधारकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन-सी रणनीतियाँ कारगर हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।
- **ज्ञान और संसाधन साझा करना**: शैक्षणिक संस्थान MSME उद्यमियों को प्रशिक्षण और शोध आधारित समाधान प्रदान कर सकते हैं, जबकि उद्योग संगठन बाजार की वास्तविकताओं और प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य की जानकारी साझा कर सकते हैं। बैंक और सरकार वित्तीय सहायता और नीतिगत समर्थन उपलब्ध करा सकते हैं।

संभावित लाभ

- MSME उद्यमियों को समय पर वित्तीय और तकनीकी सहायता मिलेगी।
- बैंकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाया जा सकेगा।
- उद्योग संगठन और शैक्षणिक संस्थान मिलकर उद्यमियों को दीर्घकालिक स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने में मदद करेंगे।
- सामूहिक प्रयासों से NPA की दर में कमी आएगी और MSME क्षेत्र का विकास अधिक संतुलित और टिकाऊ होगा।

10. चर्चा और निष्कर्ष

धनबाद जिले में MSME ऋणों की स्थिति पर किए गए इस शोध से यह स्पष्ट होता है कि समस्या अत्यंत गंभीर है और तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। **12.8% की NPA दर** राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है, जो यह दर्शाती है कि स्थानीय MSME क्षेत्र वित्तीय अस्थिरता और संरचनात्मक चुनौतियों से जूझ रहा है।

बहुआयामी कारणों का विश्लेषण

यह समस्या किसी एक कारक का परिणाम नहीं है, बल्कि आर्थिक, प्रबंधकीय, तकनीकी और संस्थागत कारकों की जटिल परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती है।

- **आर्थिक कारक**: मांग में अस्थिरता, परिचालन लागत में वृद्धि और स्थानीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी।
- **प्रबंधकीय कारक**: औपचारिक प्रबंधन संरचना का अभाव, वित्तीय योजना और नकदी प्रवाह प्रबंधन में कमजोरी।
- **तकनीकी कारक**: पुरानी मशीनरी, सीमित तकनीकी उन्नयन और डिजिटल उपकरणों का न्यूनतम उपयोग।
- **संस्थागत कारक**: बैंकिंग प्रक्रियाओं की जटिलता, ऋण निगरानी की कमी और वसूली तंत्र की धीमी गति।

बैंकिंग प्रक्रियाओं की सीमाएँ

सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि वर्तमान बैंकिंग प्रक्रियाएँ MSME क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। ये प्रक्रियाएँ मूलतः बड़े कॉर्पोरेट ऋणों के लिए डिज़ाइन की गई हैं और जब इन्हें छोटे उद्यमों पर लागू किया जाता है तो वे अप्रभावी साबित होती हैं। MSME के लिए विशेष रूप से तैयार की गई **लचीली, तेज़ और उद्यमी-केंद्रित प्रक्रियाओं** की आवश्यकता है।

ऋण स्वीकृति के बाद निगरानी और समर्थन

एक बड़ी खामी यह है कि ऋण स्वीकृति के बाद बैंकों द्वारा नियमित निगरानी और समर्थन नहीं किया जाता। उद्यमियों को केवल ऋणदाता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि बैंकों को उनके **विकास** साथी (development partners) के रूप में कार्य करना चाहिए।

- **नियमित संपर्क और सलाह**: यदि बैंक उद्यमियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें और उन्हें वित्तीय व प्रबंधकीय सलाह दें, तो कई समस्याओं को समय रहते रोका जा सकता है।
- **प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान**: बिक्री में गिरावट, नकदी प्रवाह की अस्थिरता या किश्तों में देरी जैसे संकेतों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।
- **समय पर सहायता और पुनर्गठन विकल्प**: उद्यमियों को सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्रता से पुनर्गठन योजनाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, ताकि वे संकट से उबर सकें और NPA बनने से बच सकें।

यह शोध स्पष्ट करता है कि धनबाद जिले में MSME ऋणों की उच्च NPA दर केवल वित्तीय समस्या नहीं है, बल्कि एक संरचनात्मक और प्रणालीगत चुनौती है। यदि बैंक, सरकार और उद्योग संगठन मिलकर MSME-केंद्रित प्रक्रियाएँ विकसित करें और ऋण स्वीकृति के बाद उद्यमियों को निरंतर समर्थन प्रदान करें, तो इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

मैं आपके लिए इस हिस्से को "निष्कर्ष और नीतिगत संकेत" (Conclusions and Policy Implications) शीर्षक वाले खंड के रूप में शोध-पत्र की संरचना में व्यवस्थित कर सकता हूँ, जिससे यह आपके अध्ययन की प्रस्तुति को और अधिक अकादमिक और प्रभावशाली बने।

मैं आगे आपके लिए इस निष्कर्ष को नीतिगत सिफारिशों की सारणी (Policy Recommendations Table) में भी बदल सकता हूँ, ताकि इसे नीति-निर्माताओं और बैंकों के लिए लागू करना और प्राथमिकता तय करना आसान हो।

© 2026 कल्पना कुमारी, डॉ० अशोक कुमार माज़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

तकनीकी दृष्टिकोण से, धनबाद के बैंक डिजिटल परिवर्तन में पिछड़े हुए हैं। जबकि देश के अन्य हिस्सों में फिनटेक समाधान तेजी से अपनाए जा रहे हैं, यहां अभी भी पारंपरिक तरीके प्रचलित हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म न केवल प्रक्रिया को तेज़ बना सकते हैं बल्कि बेहतर डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से जोखिम प्रबंधन को भी सुधार सकते हैं।

उद्यमियों के दृष्टिकोण से, प्रबंधकीय कौशल और वित्तीय साक्षरता में सुधार की बहुत गुंजाइश है। कई उद्यमी तकनीकी रूप से कुशल हैं लेकिन व्यावसायिक प्रबंधन में कमजोर हैं। व्यापक प्रशिक्षण और सलाहकार सेवाओं से उनकी सफलता की संभावना बढ़ सकती है।

सरकारी नीतियों में सुधार की आवश्यकता

- वर्तमान में उपलब्ध योजनाएँ या तो अपर्याप्त हैं या उनका कार्यान्वयन प्रभावी नहीं है।
- **Credit Guarantee योजना का विस्तार** आवश्यक है ताकि बैंकों को संपार्श्विक की अनुपलब्धता में भी ऋण देने में सुविधा हो और नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर मिले।
- **ब्याज सब्सिडी योजनाओं का लक्षित वितरण** किया जाना चाहिए, जिससे यह लाभ केवल उन उद्यमों तक पहुँचे जो वास्तव में व्यवहार्य हैं और वित्तीय दबाव में हैं।
- **बुनियादी ढाँचे में निवेश**—नियमित बिजली आपूर्ति, बेहतर सड़कें, औद्योगिक पार्कों का विकास—MSME की सफलता और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अनिवार्य है।

शोध की सीमाएँ

- यह अध्ययन केवल एक जिले (धनबाद) पर केंद्रित है, इसलिए इसके निष्कर्षों को अन्य क्षेत्रों पर लागू करते समय सावधानी बरतनी होगी।
- **COVID-19 के दीर्घकालिक प्रभावों** का पूर्ण आकलन अभी बाकी है, और यह MSME क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता पर गहरा असर डाल सकता है।
- भविष्य के शोध में अन्य जिलों के साथ **तुलनात्मक अध्ययन** और दीर्घकालिक रुझानों का विश्लेषण किया जाना चाहिए, ताकि व्यापक नीति-निर्माण के लिए ठोस आधार तैयार हो सके।

समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता

सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि NPA की समस्या को केवल सख्त वसूली उपायों से हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें रोकथाम पर विशेष जोर दिया जाए।

- **बेहतर ऋण मूल्यांकन**: उद्यम की व्यावसायिक योजना, नकदी प्रवाह और बाजार स्थिति का गहन विश्लेषण।
- **निरंतर समर्थन**: बैंकों को केवल ऋणदाता नहीं बल्कि उद्यमियों के विकास साथी के रूप में कार्य करना चाहिए।
- **तकनीकी उन्नयन**: MSME इकाइयों को आधुनिक मशीनरी, डिजिटल उपकरण और डेटा एनालिटिक्स अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का विकास**: सरकार, बैंक, उद्योग संगठन और शैक्षणिक संस्थान मिलकर MSME के लिए सहयोगात्मक ढाँचा तैयार करें।

निष्कर्ष

धनबाद जिले में MSME क्षेत्र की अपार संभावनाएँ हैं। यदि उचित समर्थन, लचीली नीतियाँ और आधुनिक तकनीकी साधन उपलब्ध कराए जाएँ, तो यह क्षेत्र रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का प्रमुख स्रोत बन सकता है।

मैं आपके लिए इस हिस्से को "नीतिगत संकेत और भविष्य की दिशा" (Policy Implications and Future Directions) शीर्षक वाले खंड के रूप में शोध-पत्र की संरचना में व्यवस्थित कर सकता हूँ, जिससे यह आपके अध्ययन को और अधिक अकादमिक और प्रभावशाली बना देगा।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल आर, जैन एस. फिनटेक समाधान और MSME ऋण: भारतीय संदर्भ में अवसर और चुनौतियां. भारतीय बैंकिंग शोध पत्रिका. 2024;15(2):78-95.
2. गुप्ता ए, शर्मा वी. COVID-19 का MSME क्षेत्र पर प्रभाव: झारखंड राज्य का विश्लेषण. लघु उद्योग अध्ययन त्रैमासिक. 2023;11(4):156-174.
3. कुमार आर, सिंह पी. बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति: कारण और समाधान. वित्तीय प्रबंधन जर्नल. 2024;18(1):45-67.
4. मिश्रा डी, पांडे एम. MSME उद्यमों में प्रबंधकीय चुनौतियां और NPA का संबंध. भारतीय व्यवसाय अध्ययन. 2022;9(3):234-256.
5. पटेल एन, देसाई के. ऋण वसूली तंत्र की प्रभावशीलता: भारतीय बैंकों का अनुभव. बैंकिंग और वित्त समीक्षा. 2022;14(2):112-131.
6. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट. मुंबई: RBI प्रकाशन; 2023.
7. रॉय एस, चटर्जी बी. MSME ऋण मूल्यांकन में संपार्श्विक की भूमिका: आलोचनात्मक विश्लेषण. बैंकिंग अध्ययन जर्नल. 2023;12(1):89-108.
8. शर्मा आर, वर्मा एन. भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र का योगदान. आर्थिक विकास त्रैमासिक. 2023;16(3):201-223.

© 2026 कल्पना कुमारी, डॉ० अशोक कुमार माज़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

9. सिन्हा के, कुमार वी. झारखंड में औद्योगिक विकास और चुनौतियां. क्षेत्रीय अर्थशास्त्र अध्ययन. 2024;10(2):145-167.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the author

कल्पना कुमारी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद (झारखंड) के अर्थशास्त्र विभाग में शोधार्थी हैं। उनकी शैक्षणिक रुचि विकास अर्थशास्त्र, MSME क्षेत्र, वित्तीय समावेशन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में है। वे शोध कार्यों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण कर व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं।

डॉ. अशोक कुमार माज़ी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में सह-प्राध्यापक एवं शोध निर्देशक हैं। उन्हें शिक्षण एवं शोध का व्यापक अनुभव है। उनके प्रमुख शोध क्षेत्र विकास अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय नीतियां और क्षेत्रीय विकास हैं, जिनमें उनका महत्वपूर्ण शैक्षणिक योगदान रहा है।

© 2026 कल्पना कुमारी, डॉ॰ अशोक कुमार माज़ी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/